लिए केन्द्रीय सरकार को कोई नई पर्यटन नीति प्रस्तुत की है, जिसमें कि अनिवासी भारतीयों, निजी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र को शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नई पर्यटन नीति की मुख्य-मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उक्त नीति के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी सहायता राशि प्रदान की गयी है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़द): (क) और (ख) जी, हां। गुजरात की नई पर्यटन नीति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:—

(1) पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाना।

(2) नई पर्यटन परियोजनाओं के लिए एक मुश्त प्रोत्साहन।

(3) पर्यटन सम्बन्धी आधारभूत सुविधाओं का एकीकृत विकास।

(ग) और (घ) नीति को लागू करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को, उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के गुण-दोष, पारस्परिक प्राथमिकता तथा धन की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। गुजरात सरकार ने वर्ष 1995-96 के लिए 23.00 लाख रु० के परिव्यय सहित 6 स्कीमें परियोजनाएं निर्धारित की हैं। इन परियोजनाओं/इकाइयों के संबंध में ब्यौरेवार प्रस्ताव अभी मिलने बाकी है।

Export of Cotton

236. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state.

(a) the policy adopted by Government with regard to Export of cotton;

(b) whether there has been a bumper crop of cotton during the current year;

(c) if so, whether a decision regarding export of cotton for the current year has been taken; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI KAMAL NATH): (a) Under the long term policy on cotton export which was approved by the Cabinet Committee on Export Strategy in 1990 a quota of 5 lakh bales of cotton for export is to be announced in the beginning of the cotton season. Subsequent release of actual quantity for export are guided by the requirement of the industry, availability for domestic and international market prices and other factors. The broad aims of the policy are to maintain India's presence in the international market as a reliable supplier of cotton, stablise cotton prices for domestic indistry and to provide remunerative prices to the cotton growers.

(b) It is too early in the cotton season 1995-96 (Sep-Aug) to give an acurate estimate of the cotton crop.

(c) and (d) Government of India has released 1 lakh bales of Bengal Deshi cotton for export in October this year. This is an early crop and is non spinnable, so its export will not affect the supply of cotton to the domestic spinning mills.

Changes Proposed in the Prasar Bharati Act

237. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether proposals for changes in the Prasar Bharati Act for autonomy of the electronic media have been finalised and are under the consideration of Government for approval;

(b) if so, the details of the changes proposed in the Prasar Bharati Act; and

(c) by when they are likely to be implemented?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI P.M. SAYEED): (a) to (c) Certain changes, inter-alia, in the proposed organisational structure of the Corporation are warranted in the light of the rapidly changing broad-

casting scenario because of increased international satellite broadcasting in this part of the world. The details in this regard are being finalised. No specific time frame can be indicated at present.

स्थानीय रेडियो स्टेशनों की स्थापना किया जाना

238. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्याप्त संख्या में स्थानीय रेडियो स्टेशनों की स्थापना किये जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में अब तक इस दिशा में क्या कदम उठाये गये है; और

(ग) उक्त योजना अवधि के लिए राज्यवार क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश में स्थानीय रेडियो स्टेशनों से संबंधित 59 स्कीमों का विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वयन किया जा रहा है। स्थानीय रेडियो स्टेशनों की 44 स्कीमें चालू सातवीं योजना और वार्षिक योजनाओं का हिस्सा है और 15 स्कीमें नई हैं। विभिन्न राज्यों में 38 रेडियो स्टेशन चालू कर दिए है। राज्यवार प्रयोजनाओं की स्थिति विवरण में दी गयी है।

विवरण

राज्य	स्थान जहां पर चालू किया	वे स्थान जहां कार्यान्वयनाधीन है
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	कुरनूल मरकापुरम	मकरेला
अरूणाचल प्रदेश		जीरो
असम	हाफलोंग नौगांव	दीफू
बिहार	पुर्णिया चाईबासा हजारीबाग डाल्टनगंज	
गुजरात		वडोदरा हिम्मतनगर
हरियाणा		हिसार
हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	चम्बा
जम्मू और कश्मीर	पूंछ	
कर्नाटक हॉसपेट	हॉसपेट रायचुर कारवार	बीजापुर